बिहार

18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों के बीच में रैंक

संपूर्ण रूप से	पुलिस	जेलें	न्यायपालिका	विधिक सहायता
17th	14th	6th	18th	16th

India Justice Report | 2019
Supported by TATA TRUSTS

पुलिस

श्रेणी में रैंक 14th

अंक (10 में से) 4.28

डेटा को कैसे पढ़ें : चूंकि प्रत्येक संकेतक की एक अलग इकाई होती है, इसलिए तुलना करने के लिए, हमने 1 से 10 के बैंड में राज्य के प्रदर्शन की गणना करने हेतु मूल्यों के लिए एक नया आधार स्तर तैयार किया है। लाइन ग्राफ यह दर्शाता है कि राज्य, प्रत्येक संकेतक पर, अन्य 17 बड़े- और मध्यम आकार के राज्यों के विरुद्ध किस प्रकार तुलना करता है। जितनी लंबी लाइनें होंगी, राज्य उतना ही बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। 'सबसे खराब मानऔर 'सर्वोत्तम मान' उस सूचक के उच्चतम एवं निम्नतम परिणामों को इंगित करते हैं।

बजट

	राज्य का मान	राज्य के अंक (10 में से)	सबसे खराब मान	सबसे अच्छा मान	राज्य रैंक
उपयोग किया गया मॉडर्नाईज़ेशन फंड (%, 2016-17)	46		3	80	7
प्रति व्यक्ति पुलिस पर व्यय (रुपये, 2015-16)	498		498	1,666	18

मानव संसाधन

कांस्टेबलों, रिक्ति (%, जनवरी 2017)	30.1		53.0	-6.9	13
अधिकारी, रिक्ति (%, जनवरी 2017)	38.4		62.6	8.2	16
सिविल पुलिस में अधिकारी (%, जनवरी 2017)	23.2		8.6	27.5	2

राज्य में दोनों रैंकों में उच्च स्तरीय रिक्तियां थीं। बल में 4 कर्मियों में से लगभग 1 अधिकारी के पद पर था।

विविधता

पुलिस में महिलाओं का हिस्सेदारी (%, जनवरी 2017)	8.8		2.5	12.9	6
अधिकारियों में महिलाओं का हिस्सेदारी (%, जनवरी 2017)	2.7		1.5	19.7	16
अनु. जाति अधिकारी, आरक्षित अनुपात में वास्तविक (%, जनवरी 2017)	52		32	120	15
अनु. जनजाति अधिकारी, आरक्षित अनुपात में वास्तविक (%, जनवरी 2017)	172		0	172	1
अ.पि.व. अधिकारी, आरक्षित अनुपात में वास्तविक (%, जनवरी 2017)	52		18	169	8

राज्य ने अपने अनु. जनजाति कोटे को बढ़ाया था, जो 72 प्रतिशत अंकों से कम था। लेकिन यह अपने अनु. जाति और अ.पि.व. कोटा को पूरा करने में कम पड़ गया।

अवसंरचना

जनसंख्या प्रति पुलिस स्टेशन (ग्रामीण) (जनवरी 2017)	125,977		232,896	30,445	16
जनसंख्या प्रति पुलिस स्टेशन (शहरी) (जनवरी 2017)	39,993		240,608	32,881	2
क्षेत्र प्रति पुलिस स्टेशन क्षेत्र (ग्रामीण) (वर्ग कि.मी., जनवरी 2017)	125		719	79	1
क्षेत्र प्रति पुलिस स्टेशन (शहरी) (वर्ग कि.मी., जनवरी 2017)	8		71	8	1

कार्यभार

जनसंख्या प्रति नागरिक पुलिस (व्यक्ति, जनवरी 2017)	1,663		1,663	445	18

रुझान

कुल पुलिस में महिलाएं (प्रतिशत अंक, कैलेंडर वर्ष '12-'16)	1.33		-0.65	1.33	1
कुल अधिकारियों में महिला अधिकारी (प्रतिशत अंक, कैलेंडर वर्ष '12-'16)	0.24		-0.68	1.14	9
कांस्टेबल रिक्ति (प्रतिशत अंक, कैलेंडर वर्ष '12-'16)	2.03		2.35	-4.14	15
अधिकारी रिक्ति (प्रतिशत अंक, कैलेंडर वर्ष '12-'16)	2.85		3.39	-4.53	15
व्यय में अंतर: पुलिस बनाम राज्य (प्रतिशत अंक, वित्तीय वर्ष '12-'16)	-2.37		-6.11	6.04	8

राज्य ने 5 वर्षों में कुल पुलिस बल में महिलाओं की सबसे बड़ी वृद्धि दिखाई। बल में उनकी हिस्सेदारी 3.4% से बढ़कर लगभग 9% हो गई।

डेटा स्रोत : विभिन्न पुलिस संगठन, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बी.पी.आर. एंड डी.); भारत में संघ और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त एवं राजस्व लेखे; भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक; प्राथमिक जनगणना सार, जनगणना 2011; ओपन बजट्स इंडिया।

टिप्पणियां : 1. 'जनवरी 2017' हेतु डेटा, दिनांक 1 जनवरी, 2017 तक के अनुसार है। 2. एस.सी.: अनु. जाति; एस.टी.: अनु. जनजाति; ओ.बी.सी.: अन्य पिछड़ा वर्ग। 3. पी.पी.: प्रतिशत अंक। 4. एन.ए.: उपलब्ध नहीं। 5. सी.वाई.: कैलेंडर वर्ष; एफ.वाई.: वित्तीय वर्ष। 6. सिविल पुलिस में जिला सशस्त्र रिज़र्व पुलिस भी सम्मिलित है।

जेलें

श्रेणी में रैंक 6th

अंक (10 में से) 5.61

डेटा को कैसे पढ़ें : चूंकि प्रत्येक संकेतक की एक अलग इकाई होती है, इसलिए तुलना करने के लिए, हमने 1 से 10 के बैंड में राज्य के प्रदर्शन की गणना करने हेतु मूल्यों के लिए एक नया आधार स्तर तैयार किया है। लाइन ग्राफ यह दर्शाता है कि राज्य, प्रत्येक संकेतक पर, अन्य 17 बड़े- और मध्यम आकार के राज्यों के विरुद्ध किस प्रकार तुलना करता है। जितनी लंबी लाइनें होंगी, राज्य उतना ही बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। 'सबसे खराब मानऔर 'सर्वोत्तम मान' उस सूचक के उच्चतम एवं निम्नतम परिणामों को इंगित करते हैं।

	राज्य का मान	राज्य के अंक (10 में से)	सबसे खराब मान	सबसे अच्छा मान	राज्य रैंक
बजट					
प्रति कैदी व्यय (रु., 2016-17)	34,741		14,683	41,849	5
उपयोग किया गया जेल बजट (%, 2016-17)	85		77	99	15
मानव संसाधन					
अधिकारी, रिक्ति (%, दिसंबर 2016)	52.7		70.1	-0.5	14
कैडर स्टाफ रिक्ति (%, दिसंबर 2016)	65.9		71.6	1.2	16
करेक्शनल स्टाफ रिक्ति (%, दिसंबर 2016)	46.4		100.0	0.0	9
चिकित्सा कर्मचारी, रिक्ति (%, दिसंबर 2016)	25.5		85.6	0.0	5
चिकित्सा अधिकारी, रिक्ति (%, दिसंबर 2016)	29.6		100.0	0.0	8
विविधता					
जेल स्टाफ में महिलाएं (%, दिसंबर 2016)	5.2		2.3	18.7	17
अवसंरचना					
जेल अध्यावास (%, दिसंबर 2016)	88		190	66	1
कार्यभार					
क़ैदी प्रति अधिकारी (व्यक्ति, दिसंबर 2016) कैदी	194		343	36	15
क़ैदी प्रति कैडर स्टाफ (व्यक्ति, दिसंबर 2016)	17		27	5	13
क़ैदी प्रति करेक्शनल स्टाफ (व्यक्ति, दिसम्बर 2016)	409		95,336	124	6
रुझान					
अधिकारी रिक्ति (प्रतिशत अंक, कैलेंडर वर्ष '12-'16)	-3.20		7.91	-3.45	2
कैडर स्टाफ रिक्ति (प्रतिशत अंक, कैलेंडर वर्ष '12-'16)	-3.15		5.60	-7.26	5
जेल स्टाफ में महिलाओं का हिस्सेदारी (प्रतिशत अंक, कैलेंडर वर्ष '12-'16)	-0.28		-0.28	1.46	16
क़ैदी प्रति जेल अधिकारी (%, कैलेंडर वर्ष '12-'16)	-0.4		55.6	-9.7	4
क़ैदी प्रति कैडर स्टाफ (%, कैलेंडर वर्ष '12-'16)	-4.7		14.4	-6.8	2
विचाराधीन बंदियों की हिस्सेदारी (प्रतिशत अंक, कैलेंडर वर्ष '12-'16)	0.06		1.41	-0.77	6
प्रति कैदी व्यय (%, वित्तीय वर्ष '13-'17)	23.3		1.2	65.3	3
उपयोग किया गया जेल बजट (प्रतिशत अंक, वित्तीय वर्ष '13-'17)	3.44		-2.28	4.00	2
व्यय में अंतर : जेल बनाम राज्य (प्रतिशत अंक, वित्तीय वर्ष '12-'16)	6.6		-21.8	26.3	1

राज्य में संपूर्ण जेल प्रणाली में पंगुजनक रिक्तियां थीं। लगभग 66% कैडर स्टाफ़ के पद खाली पड़े थे, जबकि जेल अधिकारी के 2 स्वीकृत पदों में से 1 खाली था।

जबकि राज्य की जेलें अति संकुलित नहीं थीं, अधूरी रिक्तियों के कारण प्रति अधिकारी / कर्मचारी अनुपात में कैदियों की संख्या अधिक थी।

राज्य में जेल कर्मचारियों में महिलाओं की सबसे कम हिस्सेदारी थी। पांच साल की अवधि में, सभी बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में महिला कर्मचारियों की उपस्थिति सबसे कम हो गई।

डेटा स्रोत : जेल सांख्यिकी भारत (पी.एस.आई), राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.); भारत में संघ और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त एवं राजस्व खाते; भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक; प्राथमिक जनगणना सार, जनगणना 2011; ओपन बजट्स इंडिया।

टिप्पणियां : 1.'दिसंबर 2016' हेतु डेटा, दिनांक 31 दिसंबर, 2016 तक के अनुसार है। 2. पी.पी.: प्रतिशत अंक। 3. एन.ए.: उपलब्ध नहीं। 4. सी.वाई.: कैलेंडर वर्ष; एफ.वाई.: वित्तीय वर्ष।

Supported by TATA TRUSTS

न्यायपालिका

श्रेणी में रैंक 18th

अंक (10 में से) 2.41

डेटा को कैसे पढ़ें : चूंकि प्रत्येक संकेतक की एक अलग इकाई होती है, इसलिए तुलना करने के लिए, हमने 1 से 10 के बैंड में राज्य के प्रदर्शन की गणना करने हेतु मूल्यों के लिए एक नया आधार स्तर तैयार किया है। लाइन ग्राफ यह दर्शाता है कि राज्य, प्रत्येक संकेतक पर, अन्य 17 बड़े- और मध्यम आकार के राज्यों के विरुद्ध किस प्रकार तुलना करता है। जितनी लंबी लाइनें होंगी, राज्य उतना ही बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। 'सबसे खराब मानऔर 'सर्वोत्तम मान' उस सूचक के उच्चतम एवं निम्नतम परिणामों को इंगित करते हैं।

	राज्य का मान	राज्य के अंक (10 में से)	सबसे खराब मान	सबसे अच्छा मान	राज्य रैंक
बजट					
न्यायपालिका पर प्रति व्यक्ति व्यय (रु., 2015-16)	62		52	201	17
मानव संसाधन					
जनसंख्या प्रति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (2016-17)	3,558,956		3,558,956	963,181	16
जनसंख्या प्रति अधीनस्थ न्यायालय न्यायाधीश (2016-17)	101,933		113,080	46,056	16
उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश रिक्ति (%, 2016-17)	44.8		59.8	26.1	9
अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीश रिक्ति (%, 2016-17)	44.0		44.0	4.5	17
उच्च न्यायालयों में कर्मचारी रिक्ति (%, 2016-17)	32.3		34.9	5.5	15
विविधता					
महिला न्यायाधीश (उच्च न्यायालय) (%, जून 2018)	6.3		0.0	19.6	9
महिला न्यायाधीश (अधीनस्थ न्यायालय) (%, जुलाई 2017)	11.5		11.5	44.0	18
अवसंरचना					
न्यायालय कक्षों की कमी (%, 2016-17, मार्च 2018)	26.6		35.1	0.0	14
कार्यभार					
लंबित प्रकरण (5-10 वर्ष) (अधीनस्थ न्यायालय) (%, अगस्त 2018)	23.69		24.04	0.99	16
लंबित प्रकरण (10+ वर्ष) (अधीनस्थ न्यायालय) (%, अगस्त 2018)	15.80		16.57	0.11	16
उच्च न्यायालयों में लंबित प्रकरण (वर्ष, सितंबर 2017)	2.9		4.3	1.7	6
अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित प्रकरण (वर्ष, अगस्त 2017)	6.3		9.5	3.7	12
प्रकरण निपटान दर (उच्च न्यायालय) (%, 2016-17)	90		70	102	6
प्रकरण निपटान दर (अधीनस्थ न्यायालय) (%, 2016-17)	87		87	129	15
रुझान					
लंबित प्रकरण (प्रति उच्च न्यायालय न्यायाधीश) (%, FY '13-'17)	7.3		17.1	-8.5	13
लंबित प्रकरण (प्रति उप-न्यायालय न्यायाधीश) (%, वित्तीय वर्ष '13-'17)	4.8		6.1	-7.9	15
कुल लंबित प्रकरण (उच्च न्यायालय) (%, वित्तीय वर्ष '13-'17	2.6		10.3	-9.5	9
कुल लंबित प्रकरण (अधीनस्थ न्यायालय) (%, वित्तीय वर्ष '13-'17	5.8		7.5	-2.7	15
न्यायाधीश रिक्ति (उच्च न्यायालय) (प्रतिशत अंक, वित्तीय वर्ष '13-'17)	5.82		6.71	-1.66	14
न्यायाधीश रिक्ति (अधीनस्थ न्यायालय) (प्रतिशत अंक, वित्तीय वर्ष '13-'17)	1.25		3.75	-4.57	11
प्रकरण निपटान दर (उच्च न्यायालय) (प्रतिशत अंक, वित्त वर्ष '13-'17)	-4.84		-4.84	4.75	15
प्रकरण निपटान दर (अधीनस्थ न्यायालय) (प्रतिशत अंक, वित्त वर्ष '13-'17)	1.59		-7.71	6.11	3
व्यय में अंतर : न्यायपालिका बनाम राज्य (प्रतिशत अंक, वित्तीय वर्ष '12-'16)	-9.81		-12.59	6.77	15

उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ अदालतों, दोनों ने ही लगभग आधे स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या के साथ कार्य किया। अनुपस्थित न्यायाधीशों के कारण प्रति न्यायाधीश अनुपात में उच्च जनसंख्या थी।

यदि अधीनस्थ न्यायालय स्तर पर रिक्त पद भरे जाते हैं, तो प्रत्येक न्यायाधीश के पास उपयोग हेतु कोर्टहॉल उपलब्ध नहीं होंगे।

5 वर्षों में, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय स्तर पर, प्रति न्यायाधीश लंबित मामलों पर, कुल लंबित मामलों और न्यायाधीशों की रिक्तियों में वृद्धि हुई है।

आंकड़ों के स्रोत : कोर्ट न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया; नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड; ई-कोर्ट सेवाएँ; उच्च न्यायालयों की वेबसाइटें; एप्रोच टू जस्टिस इन इंडिया: दक्ष (DAKSH) द्वारा एक रिपोर्ट; भारत में संघ और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व लेखे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक; प्राथमिक जनगणना सार, जनगणना 2011; सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी द्वारा दायर आवेदन; ओपन बजट्स इंडिया; न्याय विभाग।

टिप्पणियां : 1. आंकड़े 'अगस्त 2018' हेतु 23 अगस्त 2018 पर; 'सितम्बर 2017' हेतु 19 सितंबर, 2017 पर; तथा 'अगस्त 2017' हेतु 29 अगस्त, 2017 पर आधारित हैं।

2. अधी. अदालत : अधीनस्थ अदालत 3. पीपी: प्रतिशत अंक 4. एनए: उपलब्ध नहीं 5. सीवाई: कैलेंडर वर्ष; एफवाई: वित्तीय वर्ष

Supported by TATA TRUSTS

विधिक सहायता

श्रेणी में रैंक 16th

अंक (10 में से) 4.52

डेटा को कैसे पढ़ें : चूंकि प्रत्येक संकेतक की एक अलग इकाई होती है, इसलिए तुलना करने के लिए, हमने 1 से 10 के बैंड में राज्य के प्रदर्शन की गणना करने हेतु मूल्यों के लिए एक नया आधार स्तर तैयार किया है। लाइन ग्राफ यह दर्शाता है कि राज्य, प्रत्येक संकेतक पर, अन्य 17 बड़े- और मध्यम आकार के राज्यों के विरुद्ध किस प्रकार तुलना करता है। जितनी लंबी लाइनें होंगी, राज्य उतना ही बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। 'सबसे खराब मानऔर 'सर्वोत्तम मान' उस सूचक के उच्चतम एवं निम्नतम परिणामों को इंगित करते हैं।

	राज्य का मान	राज्य के अंक (10 में से)	सबसे खराब मान	सबसे अच्छा मान	राज्य रैंक
बजट					
उपयोग की गई रा.वि.से.प्रा. निधि (%, 2017-18)	50		50	98	18
विधिक सहायता व्यय में राज्य की हिस्सेदारी (%, 2017-18)	65		0	89	10
मानव संसाधन					
जि.वि.से.प्रा. में सचिव रिक्ति (%, 2019)	0.0		34.8	0.0	1
पैरा लीगल वॉलंटियर प्रति लाख जनसंख्या (संख्या, जनवरी 2019)	4.2		1.6	13.8	15
जि.वि.से.प्रा. के स्वीकृत सचिव (%, 2019)	100		100	103	1
विविधता					
महिला पैनल अधिवक्ता (%, जनवरी 2019)	22.7		7.4	40.4	4
महिला पैरा लीगल वॉलंटियर (%, जनवरी 2019)	22.3		22.3	65.7	18
अवसंरचना					
राज्य न्यायिक जिलों के % के रूप में जि.वि.से.प्रा. (%, 2019)	100		83	100	1
ग्राम प्रति विधिक सेवाएं क्लिनिक (संख्या, 2017-18)	348.9		1,603.5	6.2	17
विधिक सेवाएं क्लिनिक प्रति जेल (संख्या, 2017-18)	0.95		0.19	1.78	3
कार्यभार					
स्थायी लोक अदालत प्रकरण : प्राप्त प्रकरणों के % के रूप में निराकृत (%, 2017-18)	24		0	85	14
कुल लोक अदालतें : मुक़दमा-पूर्व प्रकरणों का निपटारा (%, 2017-18) *	81.2		7.4	92.1	2
रा.वि.से.प्रा. लोक अदालतें : लिए गए प्रकरणों में प्री-लिटिगेशन (%, 2017-18) **	12.0		0.0	93.8	5

राज्य ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की निधियों के सबसे कम उपयोग को प्रदर्शित किया।

राज्य में लगभग 350 गांवों के लिए औसतन 1 विधिक सेवा क्लिनिक था।

आंकड़ों के स्रोत : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा); प्राथमिक जनगणना सार, जनगणना 2011; प्रिज़न स्टेटिसटिक्स इंडिया (पीएसआई), राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी).
टिप्पणियां : 1. डीएलएसए : जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण; एलए : लोक अदालत; पीएलए : स्थायी लोक अदालत; पीएलवी : पैरा-लीगल वॉलंटियर; एसएलएसए : राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण।
पूर्ण संकेतक : *एलएलए + एसएसएसए एलए : विचाराधीन मामलों (%, 2017-18) में पूर्व-मुकदमेबाजी मामलों की हिस्सेदारी; ** एसएसएसए एलए : कुल लिए गए मामलों (%, 2017-18) के % के रूप में लिए गए पूर्व-मुकदमेबाजी के मामले;

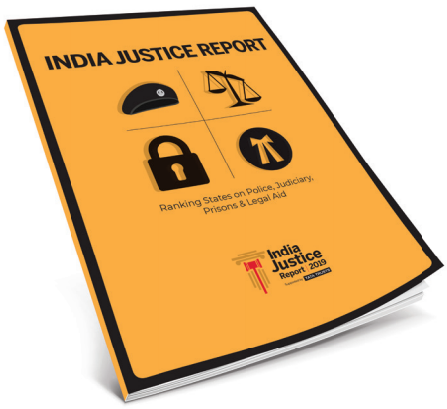

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के बारे में :

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 प्रथम व्यापक मात्रात्मक सूचकांक प्रदान करती है जो विभिन्न राज्यों में औपचारिक न्याय प्रणाली की क्षमता को पुलिस, जेलों, न्यायपालिका एवं विधिक सहायता पर संचालित औपचारिक न्याय प्रणाली की क्षमता को रैंक प्रदान करता है। इस रैंकिंग को टाटा ट्रस्ट द्वारा दक्ष, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, कॉमन कॉज, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और टी.आई.एस.एस.-प्रयास की साझेदारी में समर्थित किया गया था एवं सुसाध्य बनाया गया था।

मुख्य रिपोर्ट, रैंकिंग और कार्यपद्धति, डेटा विज़ुअलाइज़ेशन, संबंधित अनुसंधान एवं और अधिक जानकारी हेतु **www.tatatrusts.org** पर जाएं।

डेटा एवं डिज़ाइन : हाउ इंडिया लिव्स

Supported by
TATA TRUSTS